SHIKSHA SAMVAD
International Open Access Peer-Reviewed & Refereed
Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
Volume-02, Issue-02, December- 2024
www.shikshasamvad.com

"नेपाल के प्रति चीन का दृष्टिकोण और भारत"

नीतिका शर्मा
शोधार्थिनी, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग, डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्विद्यालय , अयोध्या

भगवती धर द्विवेदी
शोध निर्देशक, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग, का. सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

सारांश

भारत की हिमालयी परिक्षेत्र में अवस्थित नेपाल भू–राजनीतिक व सामरिक द्रष्टिकोण से अत्यधिक महत्त्व रखता है, जिसकी भारत के साथ आर्थिक निर्भरता एंव भारत व चीन के मध्य एक अंतस्य–राज्य के रूप में उसकी उपस्थिति भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। नेपाल का वर्तमान नाम पौराणिक काल में स्थापित निमुनी राजवंश (Nymuni Dynaty) से समबन्ध रखता है। पौराणिक कथाओं में उल्लिखित है कि महान संत ने (Ne) द्वारा नेपाल के भागमती व केशवती (नया नाम विष्णुमती) के संगम पर की गई कठोर तपस्या व अनुष्ठान के फलस्वरूप यह क्षेत्र अत्यन्त पवित्र माना जाता है। अतः मुनि ने की तपोस्थली इस क्षेत्र को नेपाल की संज्ञा प्रदान की जाती है। कई प्राचीन भारतीय हिंदू अभिलेखों से इस बात की पुष्टि होती है कि धीरे धीरे भागवती नदी के तटों के अपसरण के कारण नेपाल की वर्तमान घाटी का क्षेत्र कालांतर में भौगोलिक दृष्टि से बदलता होता चला गया।

नेपाल भारत व चीन जैसे शक्तिशाली चट्टानों के बीच स्थित एक ऐसा बर्फीला क्षेत्र है। जो अपने सामरिक द्रष्टि से दोनों महान पड़ोसियों देशों पर निर्भर है। हिमालय के मध्य स्थित नेपाल ऐसा स्थलबन्ध राष्ट्र (landlock country) है जिसका क्षेत्रफल लगभग 147181 वर्ग किलोमीटर है। हिमालय

में अवस्थित यह राष्ट्र उत्तर में चीन तिब्बतद्ध पूर्व में भारत के सिक्किम तथा दक्षिण में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्यों के मध्य स्थित है। काली नदी नेपाल को भारत से अलग करती है। तिब्बत का चीन द्वरा अधिग्रहण कर लेने से उसके द्वारा सामरिक दृष्टि से इस पठारी भू–भाग में सड़क, यातायात व संचार सुविधाओं के विस्तार करने के कारण भू–सामरिक दृष्टि से नेपाल की भू–सामरिक स्थिति अत्यन्त जटिल हो गई है। अपनी दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण आवागमन तथा व्यापारिक दृष्टि से नेपाल पूर्णरूपेण भारत पर ही आश्रित है। भारत के बंगाल की खाड़ी से ही नेपाल का व्यापार कुशलता पूर्वक सम्पन्न होता है। नेपाल तक चीन से आने वाला समान भी हिन्द महासागर के रास्ते से होते हुए पहुँचता है। इस दुर्गम क्षेत्र में आवागमन के लिए अधोलिखित दर्रे को प्रयोग में लाया जाता है।

1. ताकला खार
2. मस्तांक
3. किरोग
4. कुती
5. हटिया
6. नेलांग

नेपाल राज्य की आधारशिला राजा पृथ्वी नारायण शाह द्वारा रखी गई जिन्होने भारत के सरदार बल्लभभाई पटेल व जर्मनी के विस्मार्क की तरह ही नेपाल को एक राजैतिक रूपी माला में पिरोने का कार्य कुशलता पूर्वक किया। ध्यातव्य है कि उस समय नेपाल ने भारत के कुमाँयू, गढ़वाल व–टून घटी पर अधिकार स्थापित कर लिया था । जिसे सन् 1815–16 में हुए एंग्लों–नेपाली युद्ध के पश्चात् सुगौली संधि (Treaty of sagauli) के फलस्वरूप नेपाल द्वारा ब्रिटिश भारत को वापस करना पड़ा। यहाँ पर यह उल्लेख प्रासंगिक है कि थाईलैण्ड की तरह नेपाल पर कभी भी यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का अधिपत्य नहीं रहा।

तिब्बत–नेपाल के मध्य उत्पन्न विवादों की पृष्ठभूमि में समय–समय पर चीन न केवल नेपाल पर अपने अधिराज्य (Suzerainty) का दावा प्रस्तुत करता रहा अपितु 1792 में नेपाल द्वारा तिब्बत की प्रत्यक्ष सहायता तिब्बत के साथ स्थापित उसके सुदृढ़ सम्बन्धों का परिणाम ही है, नेपाल की सरकार ने भारत के साथ सन् 1950 में शांति व मैत्री संधि करके अपने विकास, समप्रभुता व अखण्डता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रक्षा कवच तैयार किया।

सन् 1971 के बांग्ला मुक्ति संघर्ष में चीन व अमेरिकी निकटता के फलस्वरूप नेपाल व चीन के मध्य ''कैरट व स्टिक नीति'' (Carrrot and Stick) के लक्षण दिखाई देने लगे थे। यद्यपि उक्त शक्ति संतुलन के सन्दर्भ में चीन ने नेपाल को महत्वहीन मानते हुए उसके सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ व तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देना आरंभ कर दिया। किन्तु चीन द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं में नेपाल की आर्थिक सहायता नीति भी निरंतर बनी रही।

चीन की दक्षिण एशिया सम्बन्धी पंच उंगली सम्बन्धी नीति (Five Finger Policy) में नेपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेपाल की राजनीति में भी चीन की उत्सुकता निरंतर बनी हुई है. तथा दोनों देशों के बीच प्रत्येक उच्चस्तरीय बैठकों में जहाँ एक ओर नेपाल चीन की एक चीन नीति (One china policy) एंव तिब्बत पर चीन की सम्प्रभुता सम्बन्धी पक्ष का प्रबल समर्थन किया है। वहीं चीन हर सम्भव प्रयत्नों द्वारा नेपाल में भारतीय प्रभाव को अल्प करते हुए उग्रतापूर्ण नीति पर बल दे रहा है जो की भारत और नेपाल के सम्बन्धों के मध्य चुनौती उत्पन्न करने जैसा है।

नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों को विभिन्न संधियों के माध्यम से मजबूत किया गया है, जिसमें 1950 में हस्ताक्षरित व्यापार और वाणिज्यिक संधि और शांति और मैत्री संधि शामिल हैं। इन समझौतों ने नेपाल के नागरिकों को भारत में विशेषाधिकार और अवसर प्रदान किए हैं, जिससे सीमा पार मुक्त आवागमन की परंपरा को बढ़ावा मिला है। भारत ने नेपाल में शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से इसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नेपाल की भारत पर निर्भरता उनकी साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है। हाल के सहयोग, जैसे कि बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का निर्माण और आपदा राहत प्रयास, नेपाल के विकास का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हुए, दोनों देशों को आपसी लाभ के लिए अपने साझा जल संसाधनों का लाभ उठाने के अवसरों का पता लगाना चाहिए।

चीन ने क्षेत्रीय भू–राजनीतिक परिदृश्य में भारत के प्रमुख प्रभाव को संतुलित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। 2008 में नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन के बाद, चीन ने अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और क्षेत्र में भारत के प्रभाव को स्थिर करने के अवसर का लाभ उठाया है। नेपाल के साथ आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देकर चीन का लक्ष्य अपनी भू–राजनीतिक चिंताओं को दूर करना है, खास तौर पर तिब्बत की सुरक्षा के बारे में। लगभग 1414 किलोमीटर की साझा सीमा के साथ, नेपाल में चीन की रणनीतिक भागीदारी देश की भविष्य की राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण है। चीन बीसवीं सदी के मध्य से ही नेपाल के साथ सक्रिय रूप से राजनयिक

संबंध विकसित कर रहा है। 1955 से 1989 के बीच की अवधि के दौरान, चीन ने नेपाल में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया और नेपाली क्षेत्र को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने का वचन दिया। इस प्रतिबद्धता के कारण चीन द्वारा नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं का प्रचार किया गया। 1980 के दशक में, चीन ने नेपाल में राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें पोखरा और जियांग–तिब्बत को जोड़ने वाले ट्रांस–हिमालयी राजमार्ग की स्थापना भी शामिल थी। इसके अलावा, 1987 में, नेपाल सीमा पर ल्हासा से दाजू तक सड़क बनाने की योजना बनाई गई थी। 1988 तक, चीन और नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत की सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी की गई, जिस पर नेपाल ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। 1975 से पहले नेपाल का केवल 0-7 प्रतिशत व्यापार चीन के साथ होता था, जबकि शेष 99-03 प्रतिशत भारत के साथ होता था। हालांकि, 1990 के दशक के मध्य में, चीन ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से नेपाल को अपनी आर्थिक सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि की, तथा 80 मिलियन का वार्षिक अनुदान प्रदान किया। 2005 में, चीन ने राजा ज्ञानेंद्र को उदारतापूर्वक महत्वपूर्ण मात्रा में हथियार उपलब्ध कराए, तथा भारत की आपत्तियों के बावजूद, नेपाल ने भी SAARC में चीन के शामिल होने का समर्थन किया। अगले वर्ष, चीन ने नेपाल के रक्षा मंत्री को अपने सैन्य अभ्यासों का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया तथा नेपाल को 1.3 मिलियन डॉलर के पर्याप्त सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सेनाध्यक्ष ने नेपाली सेना को गैर–घातक सैन्य सहायता के रूप में अतिरिक्त 2.6 मिलियन डॉलर की पेशकश की। चीन नेपाल राजमार्ग के पूरा होने से, ल्हासा और काठमांडू शहर आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे चीन को दक्षिण एशिया के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार मिल जाएगा। यह बुनियादी ढांचा, किंघई–तिब्बत रेलवे के साथ, चीन के साथ व्यापार के अवसरों में वृद्धि के माध्यम से नेपाल की आर्थिक वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने की क्षमता रखता है।

चीन की भागीदारी सड़क, रेलवे और अस्पताल जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से परे है। अगस्त 2008 में, चीन ने नेपाल को झांगमु–काठमांडू ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना सौंपी, जिससे दोनों देशों के बीच एक नया हाई–स्पीड सूचना मार्ग बना। इसके अतिरिक्त, चीनी ठेकेदार काठमांडू घाटी में पानी की कमी को दूर करने के लिए मेलमची जल आपूर्ति परियोजना पर काम कर रहे हैं। नेपाल ने पनबिजली परियोजनाओं में चीनी निवेश का भी स्वागत किया है, जिसकी कुल राशि लगभग 200 मिलियन रुपये है। ये कार्य नेपाल के चीन के साथ संबंधों की विविधतापूर्ण और

दीर्घकालिक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। नेपाल के प्रति चीन का सक्रिय दृष्टिकोण क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम करने के लक्ष्य से प्रेरित है।

राजा महेंद्र और माओवादी शासन के शासनकाल के दौरान, नेपाल ने लगातार चीन समर्थक नीति अपनाई है। चीन के साथ इस रणनीतिक संरेखण ने नेपाल में भारत के प्रभाव को संतुलित करने के साधन के रूप में काम किया है। भारत के खिलाफ कूटनीतिक उपकरण के रूप में चीन का उपयोग करने की यह प्रथा कोई नई बात नहीं है, जैसा कि 2005 में राजा ज्ञानेंद्र को हथियारों की आपूर्ति जैसे पिछले उदाहरणों से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, नेपाल को चीन से सैन्य सहायता भी मिली है, जिससे उनके संबंध और मजबूत हुए हैं।

इतिहास के हर दौर में नेपाल ने चीन समर्थक रुख अपनाया है, जो राजा महेंद्र के शासनकाल से ही है। हालांकि, माओवादी शासन के दौर में नेपाल ने भारत के प्रभाव को संतुलित करने के लिए चीन का खुले तौर पर एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में स्वागत किया था। भारत के खिलाफ एक रणनीतिक उपकरण के रूप में चीन का उपयोग कोई नई अवधारणा नहीं है, जैसा कि 2005 में राजा ज्ञानेंद्र द्वारा चीन से हथियार हासिल करने जैसी पिछली घटनाओं से स्पष्ट है, जिसका भारत और अमेरिका ने विरोध किया था। इसके अलावा, नेपाल को चीन से सैन्य सहायता भी मिली है, एक ऐसा रिश्ता जिसका पहले भी दस्तावेजीकरण किया जा चुका है।

चीन–नेपाल सीमा पर रेलवे संपर्क बढ़ाने से नेपाल बीजिंग से गैसोलीन आयात कर सकेगा और भारत पर उसकी निर्भरता कम होगी। नेपाल में चीन की उपस्थिति धीरे–धीरे बढ़ी है और व्यवस्थित रूप से नेपाल की भारत पर निर्भरता कम कर रही है। इसलिए, चीन नेपाल में भारत विरोधी लहर बनाने में मददगार साबित हुआ है। इसलिए, भारत को नेपाल को दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से छोटा देश नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसकी रणनीतिक और भू–राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लेने चाहिए।

निष्कर्ष एवं सुझाव

नेपाल और चीन के साथ–साथ नेपाल और भारत के बीच संबंधों की जाँच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि नेपाल और भारत के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और नृवंशविज्ञान संबंधी समानताएँ हैं, जबकि चीन के विपरीत नेपाल के साथ बहुत अधिक समानताएँ हैं। इसलिए, भारत के लिए सांस्कृतिक कूटनीति को प्राथमिकता देना अनिवार्य है, जिसमें न केवल इन साझा विशेषताओं पर बल्कि आयुर्वेद और योग जैसी अन्य समानताओं पर भी जोर दिया जाना चाहिए।

नेपाल और भारत के लिए प्राचीन और आधुनिक नेपाली भाषाओं के विकास के लिए समर्पित भाषा केंद्रों की स्थापना में सहयोग करना अनिवार्य है। यह पहल भाषा कूटनीति के रूप में कार्य करती है, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देती है। सिक्किम और बंगाल जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जहाँ नेपाली व्यापक रूप से बोली जाती है, ये भाषा केंद्र एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं, घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ा सकते हैं। हम बोधगया और लुम्बिनी को जोड़ने वाले एक प्रतिष्ठित मार्ग की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं, जिसे दुनिया भर में बौद्ध धर्म के प्रतिष्ठित मार्ग के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, हमारा लक्ष्य नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरोद्धार के साथ–साथ बौद्ध शैक्षणिक संस्थानों के एक नेटवर्क का विस्तार करना है। नेपाल और भारत में बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, हम भारत–नेपाल सीमा पर बौद्ध धर्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों की मेजबानी करने की कल्पना करते हैं ताकि पार–सांस्कृतिक संवाद और समझ को बढ़ावा दिया जा सके। नेपाल में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के मद्देनजर, कई प्राचीन मंदिर दुखद रूप से नष्ट हो गए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग, INTACH और IGNCA जैसे प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों के साथ साझेदारी में, इन अपूरणीय मूर्तियों और खंडहरों की सावधानीपूर्वक बहाली में सहायता करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और संसाधन रखता है। ये सांस्कृतिक खजाने नेपाल के लोगों के लिए बहुत महत्व रखते हैं, और उनका संरक्षण सर्वोपरि है।

भारत सरकार के पास भारत में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के इच्छुक नेपाली छात्रों को विशेष रूप से उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी अध्ययन के क्षेत्र में विशेष वित्तीय सहायता देने का अवसर है। नेपाल में शिक्षा की महंगी प्रकृति को देखते हुए, दोनों देशों के बीच एक औपचारिक समझौता पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे ज्ञान के आदान–प्रदान और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। सहयोगी प्रयासों के माध्यम से, भारतीय सहायता से नेपाल में पॉलिटेक्निक संस्थानों और कॉलेजों का निर्माण, साथ ही भारत में प्रशिक्षु के रूप में नेपाली छात्रों के लिए प्रशिक्षण के अवसर, शैक्षिक अवसरों को बहुत बढ़ा सकते हैं और क्रॉस–कल्चरल लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं। यह जरूरी है कि हम भूटान–बांग्लादेश–भारत–नेपाल (BBIN) और मोटर वाहन समझौते के अनुरूप भारत और नेपाल के बीच मौद्रिक लेन–देन को सुव्यवस्थित करें। टैरिफ बाधाओं और आर्थिक नीति बाधाओं को दूर करने के लिए खुली बातचीत को बढ़ावा देकर, हम आने वाले समय में एक एकीकृत सीमा शुल्क संघ की नींव रख सकते हैं। आइए हम एक निर्बाध और कुशल वित्तीय संबंध की दिशा में मिलकर काम करें जो दोनों देशों को लाभान्वित कर सके।

संदर्भ –

1. Eden Vansittart, Notes on Nepal (1996) P.1
2. S.Tyagi-Indo-Nepales relations, D.K Publishing house new Delhi, 1974. P.37
3. Bhattacharya abanti.china inrodss into Nepal, india's concerns, may 18,2010
4. Hari Bansh Jha, "Nepal's Border Relations with India and China", Eurasia Border Review, BRIT XII, Vol 4, No 1 (Spring 2013), p. 72
5. Satish Kumar, ÞChina*s EÛpanding Footprint in Nepal% Threats to Indiaß] Journal of Defence Studies] Vol 5- No 2- April 2011] pp- 82&83
6. https://icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=558&lid=429

SHIKSHA SAMVAD
PASSION TOWARDS EXCELLENCE

SHIKSHA SAMVAD

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed or Refereed Research Journal
ISSN: 2584-0983 (Online) Impact-Factor, RPRI-3.87
Volume-02, Issue-02, Dec.- 2024
www.shikshasamvad.com
Certificate Number-Dec-2024/10

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

नीतिका शर्मा और भगवती धर द्विवेदी

For publication of research paper title

"नेपाल के प्रति चीन का दृष्टिकोण और भारत"

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-02, Issue-02, Month December, Year- 2024, Impact-Factor, RPRI-3.87.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.shikshasamvad.com